2025:AHC-LKO:52856

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW

APPLICATION U/S 482 No. - 3075 of 2024

Divya Srivastava And Another

.....Applicant(s)

Versus

State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Civil Secrt. Lko. And Another

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Sachin Upadhyay, Shivendra S Singh Rathore
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A., Pramod Kumar Shukla

Court No. - 11

HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.

1. Heard Sri Shivendra S Singh Rathore, learned counsel for the applicants, learned AGA for the State and Sri Pramod Kumar Shukla, learned counsel for the complainant/opposite party No.2 and also perused the record.

2. Present application has been filed for the following main relief:-

> *"WHEREFORE, it is most respectfully prayed that the impugned order dated 10-04-2023, passed by the Ld. Special Chief Judicial Magistrate (Customs), Lucknow in Complaint Case No. 121766/ 2022 (Dr. Mohd. Kamran versus Divya Srivastava & Ors), whereby the applicants have been summoned u/s 500, 501 and 502 IPC, may kindly be quashed/set aside, in the interest of justice."*

3. Special Chief Judicial Magistrate (Custom), Lucknow, vide its order dated 10.04.2023 passed in Complaint Case No. 121766 of 2022 (Dr. Mohd. Kamraan Advocate vs. Divya Srivastava & Others) summoned the applicants to face the trial under Sections 500, 501 & 502 IPC. The impugned order dated 10.04.2023 reads as under:-

> "**दिनांक:-10.04.2023**
>
> पत्रावली पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।
>
> संक्षेप में परिवादी के परिवादपत्र मय शपथपत्र के कथन हैं कि परिवादी एक अधिवक्ता है तथा न्याय का पालन करने

वाला नागरिक है। परिवादी अपने परिवार सहित विपक्षीगण के द्वारा एक लेख समाचार पत्र तथा डिजिटल मीडिया में छापे जाने के कारण हुई मानहानि से क्षुब्ध है। विपक्षीगण द्वारा अपने समाचार पत्र में इस शीर्षक "मोहम्मद कामरान 'पत्रकार नहीं 'ब्लैकमेलर है: सांसद बृजभूषण सिंह" का लेख छापा गया है जिससे परिवादी तथा उसके परिवार की मानहानि हुई। विपक्षीगण संख्या-1 व 2 द संडे व्यूज़ समाचार पत्र के स्वामी व सम्पादक हैं। विपक्षीगण द्वारा उक्त मानहानिकारक लेख द संडे व्यूज़ समाचार पत्र में 6 नवम्बर 2022 को अपने आनलाइन न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित किया गया था। सोशल मीडिया पर उक्त लेख के प्रचार-प्रसार होने से परिवादी की इज्जत को क्षति पहुंची है। विपक्षीगण के द्वारा झूठे तथ्यों पर यह लेख मात्र परिवादी की बेइज्जती करने हेतु वायरल किया गया। उक्त लेख का कोई संपुष्ट आधार नहीं है। मात्र निराधार खबरों के आधार पर लिखा व छापा गया है। परिवादी ने विपक्षीगण को उक्त लेख के बाबत लीगल नोटिस प्रेषित की गयी थी, जिसका कोई जवाब विपक्षीगण द्वारा नहीं दिया गया। विपक्षीगण धारा-34, 120बी, 469, 499, 500, 501, 502 आई०पी०सी० में तलब किये जाने योग्य हैं। अत: उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण को तलब कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

परिवादपत्र के समर्थन में शपथपत्र एवं मौखिक साक्ष्य में धारा-200 दं०प्र०सं० के तहत स्वयं को परीक्षित कराया गया है तथा धारा-202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत किसी साक्षीगण को परिवादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादी द्वारा धारा-202 दं०प्र०सं० के तहत दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किये गये हैं व द संडे व्यूज़ समाचार पत्र के पंजीयन प्रमाणपत्र भी दाखिल किया गया है।

सुना तथा पत्रावली व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-200 के अन्तर्गत परीक्षित साक्षी तथा धारा-202 दं०प्र०सं० के तहत दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया। समस्त अवलोकन से विदित है कि परिवादी ने विपक्षीगण पर उनके समाचारपत्र मे तस्वीर के साथ परिवादी के बारे में अपशब्द छापकर उसकी मानहानि की है। परिवादी द्वारा इसके समर्थन में समाचार पत्र की छायाप्रति भी पत्रावली पर दाखिल की हैं, जिसमें उसके विरूद्ध कथित अपशब्द कहे गये हैं। मुख्यत: परिवादी द्वारा विपक्षीगण को धारा-500, 501, 502, 469, 499, 120बी आई०पी०सी० में तलब किये जाने की याचना की गयी है। जहां तक धारा-499 आई०पी०सी० का प्रश्न है, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि विपक्षी द्वारा आशयित शब्दों द्वारा या संकेतो द्वारा या दृष्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाये। धारा-501 आई०पी०सी० मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करने के अपराध के बारे में प्रावधान करती है। धारा-502 आई०पी०सी० मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचने के अपराध का प्रावधान करती है। परिवाद पत्र तथा परिवादी के बयानों से यह प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि विपक्षीगण ने ऐसे तथ्य अपने समाचार पत्र में छापे हैं, जो परिवादी की मानहानि करते हैं तथा समाज के समक्ष परिवादी की इज्जत को धूमिल करते हैं, परन्तु धारा-469 आई०पी०सी० के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा कोई संपुष्ट साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। चूंकि धारा-469 आई०पी०सी० हेतु परिवादी को सर्वप्रथम कूटरचना प्रथम दृष्टया साबित करनी होती है, जोकि परिवादी द्वारा नहीं की गयी है। उपरोक्त परिशीलन से प्रथम दृष्टया विपक्षी संख्या-1 व 2 दिव्या श्रीवास्तव व संजय श्रीवास्तव उर्फ संजय पुरबिया को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: विपक्षी संख्या-1 व 2 दिव्या श्रीवास्तव व संजय श्रीवास्तव उर्फ संजय पुरबिया को प्रथम दृष्टया अन्तर्गत धारा-500, 501, 502 आई०पी०सी० के अपराध के विचारण के लिये तलब किया समीचीन प्रतीत होता है तथा अन्य किसी अपराध का बनना प्रथम दृष्ट्या नहीं पाया जाता है।

आदेश

विपक्षी संख्या-1 व 2 दिव्या श्रीवास्तव व संजय श्रीवास्तव उर्फ संजय पुरबिया को अन्तर्गत धारा-500, 501, 502 आई०पी०सी० के अपराध के विचारण हेतु इस न्यायालय में तलब किया जाता है। परिवादी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के प्राविधान के अन्तर्गत समुचित पैरवी करें और साक्षीगण की सूची भी प्रस्तुत करें। कार्यालय लिपिक यह सुनिश्चित करें कि जब तक परिवादी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के प्राविधानों के अन्तर्गत समुचित रूप से पैरवी नहीं की जाती है तो उक्त दशा में आदेशिका जारी न करें। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक

05.05.2023 को पेश हो।"

4. For the purposes of seeking interference with the impugned order dated 10.04.2023, Shri Shivendra Shivam Singh Rathore, learned counsel for the applicants submitted that the Magistrate in accordance with various pronouncements on the issue ought to have applied his mind to the case set up in the complaint, as well as the statement(s) recorded in terms of Sections 200 and 202 CrPC, before summoning an accused in exercise of power under Section 204 CrPC. The Magistrate was/is also under an obligation to consider the relevant law on the issue. In the instant case, however, the Magistrate has failed to apply his mind as required for the purposes of summoning an accused in exercise of power under Section 204 CrPC and therefore, interference in the summoning order dated 10.04.2023 is required.

5. In continuation of the above, it is stated that for summoning an accused for committing an offense under Sections 500, 501, and 502 IPC, the concerned Court is required to consider the relevant provisions, including Section 500 and the exceptions provided therein, as well as the law settled on the issue in various pronouncements by the Hon'ble Apex Court, as well as by this Court.

6. It is further stated that a news item was published on 06.11.2022 in the newspaper known as "Sunday Views," of which. the applicant No.1-Divya Srivastava, is the owner and applicant No.2-Sanjay Srivastava, husband of applicant No.1, is the editor. This news item, in fact, was based upon two letters dated 25.09.2022 written by one Member of Parliament namely Brij Bhushan Sharan Singh to the Hon'ble Chief Minister and Chief Secretary of Uttar Pradesh, wherein allegations were leveled against opposite party No. 2 wherein in nutshell it is stated that against the opposite party No. 2 an FIR was lodged by one Dayashankar alleging therein that the opposite party No. 2 is a blackmailer and against the opposite party No. 2 various criminal cases pertaining to hatching of criminal conspiracy of exhortation, intimidation, theft and molestation are pending and according to first para of letter dated 25.09.2022 the opposite party No. 2 is a blackmailer.

7. It is further stated that the opposite party No. 2, being aggrieved by the two aforesaid letters dated 25.09.2022 written by Member of Parliament namely Brij Bhushan Sharan Singh, filed a Complaint Case No. 80654 of 2023 (Dr. Mohd. Kamran vs. Brij Bhushan Sharan Singh) and the Magistrate

concerned, considering the contents of the complaint and the statement(s) recorded before it in terms of Sections 200 and 202 CrPC, respectively, passed the summoning order dated 10.01.2024 against Brij Bhushan Sharan Singh requiring him to face trial. This summoning order dated 10.01.2024 was challenged by means of APPLICATION U/S 482 No. - 1604 of 2024 (Brij Bhushan Sharan Singh vs. State of U.P. And Another) and this court, after considering the relevant provisions including Section(s) 499 and 500 IPC as also various pronouncements on the issue, decided the case vide order dated 12.03.2024. Vide order dated 12.03.2024, this Court set aside the order of summoning dated 10.01.2024 passed by the Magistrate and also quashed the proceedings of the case. The order of this Court dated 12.03.2024 was challenged before the Hon'ble Apex Court by means of Special Leave to Appeal (Crl.) No. 9615 of 2024 (Mohd. Kamran vs. State of U.P. & Another) and the said appeal has already been dismissed by the Hon'ble Apex Court vide order dated 29.07.2024. The order dated 29.07.2024 is extracted here-in-under:-

> *"Upon hearing the counsel the Court made the following*
>
> *ORDER*
>
> *Permission to appear and argue in person is granted.*
>
> *We do not find any ground to interfere with the impugned order passed by the High Court, as the submission made by the learned counsel appearing for the petitioner that the petition to quash has been filed by a third party is not factually correct as both the petition filed invoking Section 482 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the impugned judgment refer to the name of respondent No.2.*
>
> *The Special Leave Petition is, accordingly, dismissed.*
>
> *Pending application(s), if any, shall stand disposed of."*

8. It is also stated that in the aforesaid background of the case and the settled legal proposition, including the judgment(s) passed in the case(s) of ***Afshan Meerza vs. State of West Bengal and Another; 2022 SCC OnLine Cal 4126, GHCL Employees Stock Option Trust vs. India Infoline Ltd.; (2013) 4 SCC 505; Criminal Appeal No. 817 of 2025 [Arising out of SLP (Crl.) No.16153 of 2024] (Neelam Raaj vs. M/s Bid and Hammer Auctioneers Pvt. Ltd.) dated 18.02.2025, Laloo Prasad vs. State of Bihar & Anr. 1996 SCC OnLine Pat 471, Criminal Appeal No(s) [Arising out of SLP (Crl.)***

No(s). 3180 of 2020 (Sanjay Upadhya vs. Anand Dubey) dated 29.01.2024, Google India Pvt. Ltd. vs. Visaka Industries; (2020) 4 SCC 162, Jawaharlal Darda and Others vs. Manoharrao Ganpatrao Kapsikar and Another; (1998) 4 SCC 112 and Application U/S 482 No. 6048 of 2019 (Aroon Purie vs. State of U.P. and Another), the Magistrate ought not to have summoned the accused by the impugned order.

9. It is also stated that summoning order dated 10.04.2023, impugned herein, is an unreasoned order as all the aspects of the case including the relevant law has not been considered while passing the same by the Magistrate concerned. Prayer is to cause interference.

10. Shri Pramod Kumar Shukla, who appeared for the opposing party No.2 opposed the present application. However, he could not dispute the fact that the order in question is not a reasoned and speaking order. On merits of the case, he has placed reliance on the judgments passed in ***Writ - C No. 20672 of 2018 (Dhananjay Singh vs. Union of India And 5 Others), Application U/S 482 No. 10431 of 2021 (Rajesh Churiwala vs. State of U.P. and Another), Application U/S 482 No. 1531 of 2023 (Manish Kumar Pandey vs. State of U.P. And 2 Others) and Criminal Misc. Bail Application No. 6712 of 2024 (Amit Maurya @ Amit Kumar Singh vs. State of U.P.).***

11. Considering the aforesaid aspects of the case, as also the judgment(s) referred above, and also the prayer sought at this stage in the instant application, this Court finds that interference is required in the matter as to the view of this Court the Magistrate while passing the impugned order dated 10.04.2023 has not considered all the aspects of the case including the law on the issue. Accordingly, the application is **allowed.** The impugned order dated 10.04.2023 passed by the Special Chief Judicial Magistrate (Custom), Lucknow, is hereby set aside. The matter is remanded back to the Magistrate concerned to pass afresh order, after considering the entire aspects of the case, including the law referred above, by means of reasoned and speaking order.

September 3, 2025
Vinay/-

(Saurabh Lavania,J.)

Digitally signed by :-
VINAY KUMAR
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench